

मसौदा निदेशों पर प्राप्त प्रमुख फीडबैक पर वक्तव्य

विषय : प्राधिकृत डीलर श्रेणी - । बैंकों के लिए रिपोर्टिंग अनुदेश

1. अनुबंध : रिपोर्टिंग इकाई

मसौदा निदेशों का अनुबंध पैरा 1 : एक प्राधिकृत डीलर श्रेणी - । बैंक अपने अपतटीय संबंधित पक्षों द्वारा किए गए आईएनआर से जुड़े ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाओं के आवश्यक विवरणों की रिपोर्ट क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) के व्यापार भंडार (ट्रेड डिपोजिटरी) को देगा। प्राधिकृत डीलर श्रेणी - । बैंक का संबंधित पक्ष भी अपने द्वारा किए गए ऐसे डेरिवेटिव के विवरण को स्वतंत्र रूप से सीसीआईएल के टीआर को रिपोर्ट करने का विकल्प चुन सकता है।

(i) फीडबैक : फीडबैक में प्राधिकृत डीलर श्रेणी - । बैंकों के संबंधित पक्षों द्वारा वैश्विक रूप से किए गए भारतीय रुपया से जुड़े विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाओं की रिपोर्ट करने की आवश्यकता के अनुपालन में परिचालनात्मक चुनौतियों सहित कई कठिनाइयों रेखांकित किया गया है।

आरबीआई की टिप्पणियाँ : स्वीकार नहीं किया गया। प्राधिकृत डीलर श्रेणी - । बैंकों और उनके संबंधित पक्षों द्वारा किए गए भारतीय रुपये से जुड़े विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाओं की रिपोर्टिंग को अनिवार्य करने का उद्देश्य पारदर्शिता में सुधार करना और विदेशी मुद्रा बाजार में कुशल मूल्य-निर्धारण को सक्षम करना है। कुछ स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलर पहले से ही समान रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का अनुपालन कर रहे हैं। परिचालनात्मक चिंताओं को दूर करने के लिए, आवश्यकताओं के क्रमबद्ध कार्यान्वयन और एक निर्दिष्ट सीमा से नीचे के ट्रेडो को बाहर रखने सहित पर्याप्त लचीलापन प्रदान किया गया है।

(ii) फीडबैक : भारतीय बैंक शाखाएं, विदेशी बैंकों की अलग-अलग कानूनी इकाइयां हैं और उनके अपतटीय संबंधित पक्षों के डेटा या व्यापारिक गतिविधियों पर दृश्यता या नियंत्रण नहीं हो सकता है।

आरबीआई की टिप्पणियाँ : इस पर विचार नहीं किया गया क्योंकि यह चिंता पहले ही दूर हो चुकी है। इन निदेशों में प्राधिकृत डीलर श्रेणी - । बैंकों के अपतटीय संबंधित पक्षों को स्वतंत्र रूप से सीसीआईएल के टीआर को कवर किए गए लेन-देन की रिपोर्ट करने का प्रावधान है, यदि ऐसा अपेक्षित हो।

2. अनुबंध : संबंधित पक्ष

मसौदा निदेशों के अनुबंध पैरा 2 : इन निदेशों के प्रयोजन के लिए, शब्द "संबंधित पक्ष" का वही अर्थ होगा जो भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 24 - संबंधित पक्ष प्रकटीकरण या अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक (आईएएस) 24 - संबंधित पक्ष प्रकटीकरण या किसी भी अन्य समकक्ष लेखांकन मानक में निर्दिष्ट है। बशर्ते कि शब्द 'संबंधित पक्ष' सहयोगियों को बाहर कर देगा, जैसा कि इंड एएस 24 या आईएएस 24 अन्य समकक्ष लेखांकन मानक में निर्दिष्ट है।

फीडबैक : निदेशों का दायरा प्राधिकृत डीलर श्रेणी -। बैंकों से आगे उनकी संबद्ध इकाइयों तक नहीं बढ़ाया जाए। रिपोर्टिंग प्राधिकृत डीलर श्रेणी -। बैंकों और उनकी अपतटीय शाखाओं तक सीमित हो।

आरबीआई टिप्पणियाँ : विचार नहीं किया गया, इस चिंता को पहले ही आंशिक रूप से संबोधित किया गया है। निदेशों में पहले से ही संबंधित पक्ष की परिभाषा से सहयोगियों को बाहर रखने का प्रावधान है।

3. अनुबंध : लेनदेन का कवरेज

मसौदा निदेशों का अनुबंध पैरा 3 : भारत में प्राधिकृत डीलर श्रेणी -। बैंक के संबंधित पक्षों द्वारा वैश्विक स्तर पर की गई आईएनआर से जुड़ी सभी ओटीसी विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाओं की रिपोर्ट, टीआर को की जाएगी। इन निदेशों के प्रयोजन के लिए, ओटीसी डेरिवेटिव का अर्थ उन डेरिवेटिव के अलावा अन्य डेरिवेटिव होंगे जो स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार करते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) पर कारोबार किए गए डेरिवेटिव शामिल होंगे।

फीडबैक : फीडबैक में इस बारे में स्पष्टता के लिए अनुरोध किया गया कि क्या गैर-सुपुर्दगी योग्य वायदे भी कवर किए गए लेनदेन के तहत शामिल हैं।

आरबीआई टिप्पणियाँ : स्वीकृत। यह स्पष्ट किया गया है कि भारतीय रुपये से जुड़ी सुपुर्दगी योग्य और गैर-सुपुर्दगी योग्य दोनों विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाएं कवर किए गए लेनदेन के दायरे में हैं।

4. अनुबंध : रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ

मसौदा निदेशों का अनुबंध पैरा 4 (iii) : एक प्राधिकृत डीलर श्रेणी -। बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि:

ए) इन निदेशों को जारी करने की तारीख के 12 महीने बाद से, इसके द्वारा रिपोर्ट किए गए लेन-देन, इसके संबंधित पक्षों द्वारा की गई आईएनआर से जुड़ी सभी विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाओं के कल्पित मूल्य का कम से कम 70 प्रतिशत हैं;

(बी) इन निदेशों को जारी करने की तारीख के 18 महीने बाद से, इसके द्वारा सूचित किए गए लेन-देन अपने संबंधित पक्षों द्वारा की गई आईएनआर से जुड़ी सभी विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाओं के कल्पित मूल्य का कम से कम 80 प्रतिशत हैं; और

(सी) इन निदेशों के जारी होने की तारीख के 24 महीने के बाद से, इसके द्वारा सूचित किए गए लेन-देन अपने संबंधित पक्षों द्वारा की गई आईएनआर से जुड़ी सभी विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाओं के कल्पित मूल्य का कम से कम 90 प्रतिशत हैं।

फीडबैक : फीडबैक में परिचालनात्मक चुनौतियों पर विचार करते हुए आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए एक विस्तारित समयसीमा के लिए अनुरोध किया गया ।

आरबीआई टिप्पणियाँ : स्वीकृत। रिपोर्टिंग आवश्यकताएं 1 जुलाई, 2027 से शुरू होंगी और चरणों में लागू होंगी।